

यमुना, नर्मदा और झेलम सहित 13 नदियों का होगा संरक्षण

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने संभाला जिम्मा, डीपीआर जारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान को मिली शुरुआती सफलता के बाद केंद्र ने अब यमुना, नर्मदा, झेलम और महानदी सहित देश की 13 प्रमुख नदियों के संरक्षण का भी फैसला लिया है। इसका जिम्मा फिलहाल वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने संभाला है। इसने 24 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों से होकर बहने वाली इन नदियों के संरक्षण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। इस पर आने वाले वर्षों में करीब 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। इस पूरी योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर होगी, जबकि केंद्र इस पर निगरानी रखेगा।



यह भी जानें

44,954 किलोमीटर है इन नदियों की कुल लंबाई

49.01% के बराबर है यह बेसिन देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के

16,11,149 वर्ग किलोमीटर है इन 13 नदियों का बेसिन क्षेत्र

4,68,222 वर्ग किमी है इस बेसिन में फारेस्ट बफर भौगोलिक क्षेत्र

पौधारोपण किया जाएगा। इससे वन क्षेत्र में 7,417 वर्ग किमी क्षेत्रफल की वृद्धि होने की उम्मीद है। साथ ही अगले 10 वर्षों में पौधारोपण से करीब 50.21 मिलियन टन कार्बन डाई आक्साइड को सोखने में मदद मिलेगी। वहीं, 20 वर्षों में 74.76 मिलियन टन कार्बन डाई आक्साइड को सोखने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री

भूपेंद्र यादव ने सोमवार को 13 नदियों के संरक्षण से जुड़ी डीपीआर जारी की। उन्होंने कहा कि इन 13 प्रमुख नदियों के साथ इनकी सहायक 202 नदियों के संरक्षण को भी इस मुहिम में शामिल करना होगा। संकेत दिया कि इसकी शुरुआत नर्मदा से की जा सकती है। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गंगा के संरक्षण को लेकर चल रही मुहिम का जिक्र किया। कहा कि नमामि गंगे से पहले भी गंगा को स्वच्छ बनाने की कई योजनाएं चलाई गई थीं। लेकिन, जनभागीदारी न होने के चलते योजनाएं विफल रहीं। उन्होंने दावा किया कि गंगा मौजूदा समय में दुनिया की 10 सबसे स्वच्छ नदियों में एक है। हालांकि, हमारी कोशिश इसे दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी का दर्जा दिलाने तक जारी रहेगी। कार्यक्रम को वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने भी संबोधित किया।

इन 13 नदियों का होगा संरक्षण: जिन 13 प्रमुख नदियों के संरक्षण का डीपीआर तैयार किया गया है, उनमें झेलम, सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी शामिल हैं।

खास बात यह है कि इस पूरी योजना को भविष्य की चुनौतियों से निपटने सहित काप-26 में जताई गई प्रतिबद्धता को पूरा करने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसके तहत वर्ष 2030 तक भारत ने अपने अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक अरब टन कम करने सहित वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में वानिकी के जरिये 13 नदियों के संरक्षण की जो योजना बनाई गई है, उसके तहत नदियों के दोनों किनारों पर सघन